पंचायतों के मजबूत होने से प्रदेश मजबूत होगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रदेश के सातों संभाग के प्रशासकों के साथ संवाद किया

जयपुर, 17 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच गांव की आवाज और ग्राम पंचायत शासन की पहली सीढ़ी है। पंचायतों के सशक्त होने से ही प्रदेश मजबूत होगा, क्योंकि विकास का पथ गांवों से होकर ही गुजरता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र-'सबका साथ, सबका विकास' को साकार करते हुए गांवों का सशक्तीकरण कर रही है।

शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के सातों संभागों की ग्राम पंचायतों के प्रशासकों (निवर्तमान सरपंचों) के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरपंच कोई पद नहीं, बल्कि सेवा और संकल्प का माध्यम है। सरपंच वह पहला व्यक्ति होता है, जिसके पास गांव का हर नागरिक उम्मीद लेकर आता है। किसान सम्मान निधि, पेंशन, एमएसपी, पेयजल, बिजली, आवास, शौचालय निर्माण, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केन्द्र जैसी जरूरतों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए गांव सर्वप्रथम सरपंच की ओर ही देखता है। उन्होंने कहा कि सरकार के जनहितैषी निर्णयों और योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुंच रहा है, यह सरपंच ही बेहतर तरीके से जानता है। इस स्थिति में उनका फीडबैक बेहद महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सातों संभागों की ग्राम पंचायतों के निवर्तमान सरपंचों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम, राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़ वाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह पंचायतीराज व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर अटल ज्ञान केन्द्र की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने नवगठित 8 जिलों में नई जिला परिषदों का गठन किया है। इसी प्रकार पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन एवं नवसृजन के तहत, 85 नई पंचायत समितियां एवं 3 हजार 417 नई ग्राम पंचायतें बनायी गयी हैं। हमने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर भी प्रशासक के तौर पर सरपंचों को नियुक्त किया, ताकि आपके अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे गांवों को मिल सके। शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में संचालित मनरेगा योजना में सुधार करते हुए विकसित भारत गांरटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू कर ग्रामीण विकास का नया रोडमैप तैयार किया है।

> ■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व जवाबदेह पंचायतीराज व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत कर रही है।

मुख्यमंत्री ने निवर्तमान सरपंचों से अपील कि वे केन्द्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं और अंतिम पंक्ति तक इनका लाभ मिलना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रशासकों ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों एवं आगामी बजट के संबंध में अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने उन्हें महत्वपूर्ण सुझावों पर नियमानुसार उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम, राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर गढ़ वाल सहित, बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों के प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) उपस्थित थे।

शिंदे सेना को ठाणे में अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के रूप में मिले दबदबे के चलते, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि शिंदे, भाजपा की सीटों के लगभग एक-तिहाई पर रहने के बावजूद, अपनी पार्टी से मेयर बनाए जाने पर जोर दे सकते हैं।

शिंदे गुट के प्रवक्ताओं और अन्य नेताओं ने, बीएमसी में अविभाजित सेना के लम्बे शासन का हवाला देते हुए, यह भी संकेत दिया है कि "मुंबई का मेयर शिवसेना (शिंदे गुट) से होना चाहिए, क्योंकि यह बालासाहेब (बाल ठाकरे) की विरासत है।"

नतीजे काफी हद तक स्पष्ट होने के बाद शिंदे का रुख अपेक्षाकृत सतर्क दिखा। शिंदे 2024 में भाजपा की 132 सीटों के मुकाबले 57 विधानसभा सीटें जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री पद हासिल नहीं कर पाए थे।

उन्होंने मेयर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "हमारा एजेंडा विकास है। हमने महायुति (ग्रैंड अलायंस) के रूप में चुनाव लड़ा है और मुंबई के हित में क्या सबसे अच्छा है, यह तय करने के लिए हम साथ बैठेंगे।"

इस गोल-मोल जवाब ने कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, जिसमें शिंदे अपनी पार्टी के किसी नेता को ढाई वर्ष के लिए मेयर बनवाएं और शेष आधा कार्यकाल भाजपा को मिले।

> ■ शिंदे, इस बार पर वो ही गलती भी नहीं दोहराना चाहते, जो 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद की थी। तब, सेना ने 57 सीटें जीती थी तथा भाजपा ने 132, पर, शिंदे ने मु.मंत्री पद के लिए दावेदारी पुरजोर ढंग से पेश की थी, अपने, वोटों को निर्णायक मानकर। पर, शिंदे का यह प्रयास बुरी तरह विफल हुआ था और उन्हें काफी राजनीतिक हानि हुई थी। इस बार, बीएमसी के चुनाव में शिंदे सार्वजनिक रूप से गंभीर सी छवि बनाए हुए हैं और कह रहे हैं "हमने (भाजपा व शिंदे ग्रुप) ने महायुति के गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा है। अतः, हम बैठकर निर्णय लेंगे, जो मुंबई के हित में होगा।"

विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा के पक्ष में एक बात यह हो सकती है कि शिंदे सेना ने अपने पार्टी प्रमुख के गढ़ ठाणे में शानदार प्रदर्शन किया है। 131 सदस्यीय ठाणे नगर निगम में पार्टी 70 से अधिक सीटों के साथ 66 के बहुमत आंकड़े से काफी ऊपर है और वहाँ वह मेयर चुन सकती है, जबकि भाजपा के पास वहां सिर्फ 28 सदस्य हैं।

मुंबई का उपनगर होने के नाते ठाणे का अपना महत्व है। इससे शिंदे बीएमसी में प्रमुख समितियों, खासतौर पर बेहद अहम स्थायी समिति, की कमान अपनी पार्टी को दिलाने पर संतोष कर सकते हैं। एक विश्लेषक ने कहा, "किसी भी स्थिति में, यदि शिंदे आसानी से मेयर पद भाजपा को सौंपने के लिए राजी हो जाते है, तो इससे उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जा सकता है। इसलिए, कम से कम उप-महापौर पद, स्थायी समिति के अध्यक्ष पद और महत्वपूर्ण वार्डों को लेकर पर्दे के पीछे तीखी बातचीत होना लगभग तय है।"

ईरान में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लोकतांत्रिक ईरान साझा मूल्यों के आधार पर साझेदारियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध होगा। उन्होंने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, यह स्वाभाविक ही है कि एक लोकतांत्रिक ईरान संप्रभुता और स्वतंत्रता के संदर्भ में उन देशों के साथ सर्वोत्तम संभव संबंध चाहता है, जो समान मूल्यों का पालन करते हों और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे साथ काम कर सकें और साझेदारी कर सकें।"उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए गहरे अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है और इस संदर्भ में भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार सिद्ध होगा। उन्होंने कहा, "हमारे सामने कई वैश्विक चुनौतियां हैं, ऊर्जा के मुद्दे हैं, जनसंख्या के मुद्दे हैं, ऊर्जा की कमी है और जल संकट भी है।" पहलवी ने भारत की तकनीकी क्षमताओं की भी सराहना की और कहा, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है। मेरा मानना है कि यही वे चीजें हैं, जो हमें हर उस दिशा में मदद करेंगी, जिस पर हमें ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।"

ममता बनर्जी ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जांच में हस्तक्षेप के ठोस आरोपों से घिरी ममता बनर्जी ध्यान भटकाने और न्याय से बचने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। उनके निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की जांच पर रोक लगाने और ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया और ममता बनर्जी तथा पश्चिम बंगाल पुलिस दोनों को 3 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उस घेराव और हंगामे की भी कड़ी आलोचना की, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में हुआ था, जहां ईडी ने मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद स्थानीय पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने ईडी की जांच में हस्तक्षेप किया, उनका काम रुकवाया और मामले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण सामग्री जांच स्थल से उठा ली थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में ईडी की याचिका पर सुनवाई तक नहीं हो सकी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने अदालत कक्ष को घेर लिया था और ईडी के वकीलों को अंदर तक पहुंचने नहीं दिया। नतीजतन, उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं ने अदालत कक्ष को एक सार्वजनिक स्थल में बदल दिया था, मानो वह दिल्ली का जंतर-मंतर हो।

अब यह देखना बाकी है कि क्या ममता बनर्जी इस बार भी इस सबसे गंभीर किस्म के दुराचार से बिना दंड के बच निकलने में सफल होती हैं या नहीं। यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि केन्द्र सरकार उनके आचरण को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए कितनी गंभीरता से कदम उठाती है।

26 जनवरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह दिल्ली सहित, देश के प्रमुख शहरों को को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के अनुसार, पंजाब के गैंगस्टर विदेश से काम कर रहे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए फुट सोल्जर के तौर पर काम कर रहे हैं। आरोप है कि ये हैंडलर्स अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़ने के लिए आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट में कहा गया है कि ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकवादी तत्वों से संबंध बना रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड से पहले, उत्तरी जिला पुलिस ने विभिन्न हितधारकों और एजेंसियों की तैयारी और प्रतिक्रिया समय की जांच करने के लिए संवेदनशील और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मॉक ड्रिल की एक श्रृंखला आयोजित की।

बांग्लादेश में एक और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का मालिक था। यह दुकान नगरपालिका इलाके के पास बरनगर रोड पर स्थित है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 11 बजे मसूम मिया (28) दुकान में आया। किसी मामूली बात को लेकर उसका दुकान में काम करने वाले 17 साल के कर्मचारी अनंत दास से विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। कुछ देर बाद मसूम मिया के माता-पिता, मोहम्मद स्वपन मिया (55) और मजीदा खातून (45) मौके पर पहुंचे और झगड़े में शामिल हो गए। जब दुकान मालिक लिटन चंद्र घोष ने बीच-बचाव कर अपने कर्मचारी को बचाने की कोशिश की, तो हमलावरों ने लिटन के सिर पर फावड़े से वार कर दिया। पुलिस के मुताबिक, चोट इतनी गंभीर थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बांग्लादेश में बीते एक महीने में अब तक 9 हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी हैं।

'प.बंगाल में मुम्बई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बंगाली में कहा, इस तृणमूल सरकार को बदलने की ज़रूरत है।

प्रधानमंत्री ने मालदा की रैली में कहा कि निर्दयी और क्रूर तृणमूल सरकार जनता के पैसे की लूट कर रही है और केंद्र की सहायता को बंगाल के लोगों तक पहुंचने से रोक रही है। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल की हार और भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही बंगाल में विकास होगा।

आईसीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खिलाड़ियों को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

यह तथ्य कि भारतीय नागरिकता वाले एक आईसीसी अधिकारी समय पर बांग्लादेश की यात्रा के लिए वीज़ा हासिल नहीं कर सके, दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात को दर्शाता है। आईसीसी ने वीज़ा मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, हालांकि कुछ निराशा तो है।

टी 20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब तीन सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में बांग्लादेश और आईसीसी दोनों के लिए इस गतिरोध को खत्म कर किसी समाधान तक पहुंचने की घड़ी तेज़ी से टिक-टिक कर रही है।

इंडिगो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने अपनी कार्रवाई के लिए सिर्फ इन्हीं तीन दिनों को आधार बनाया है। जांच समिति ने 26 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

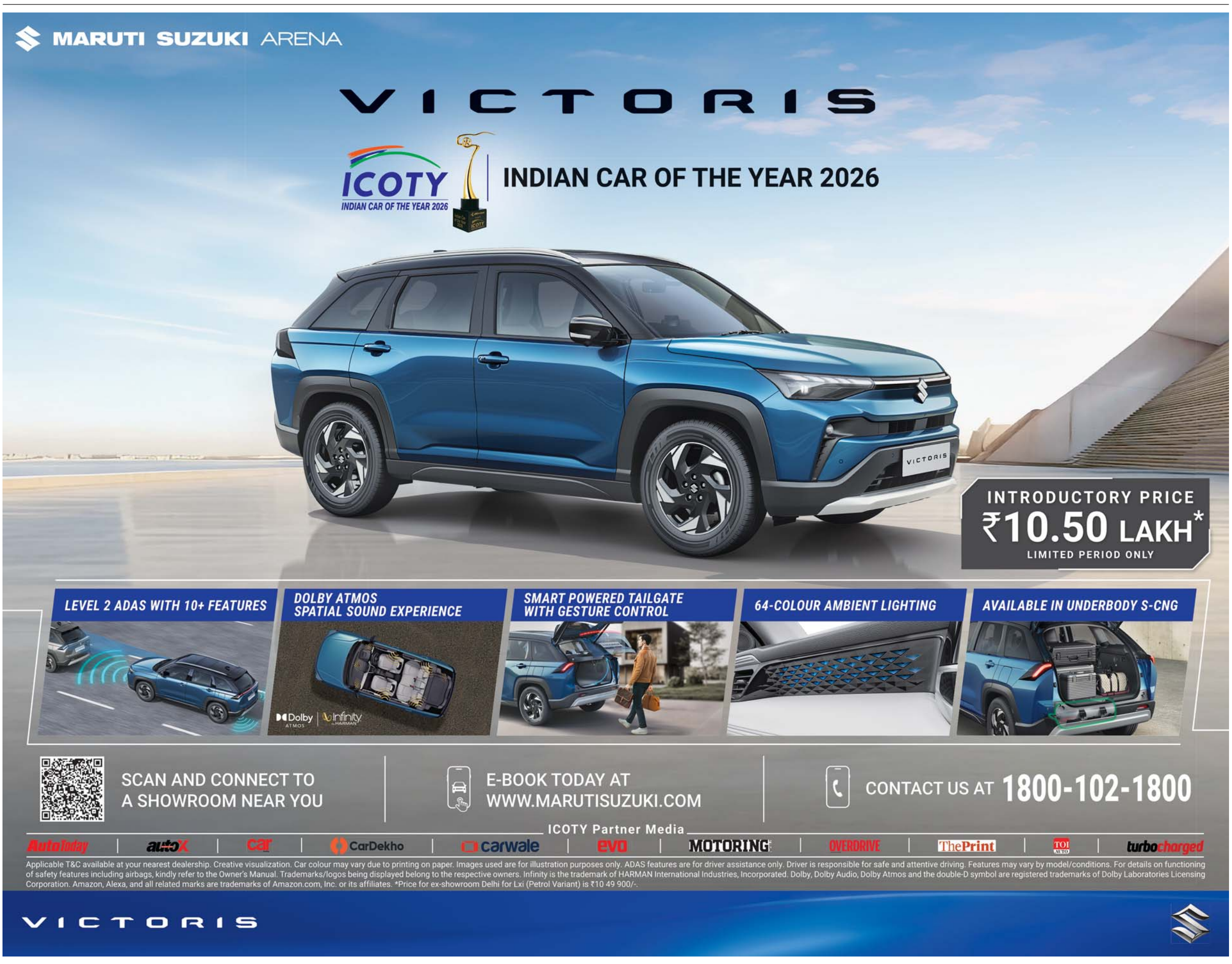

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908